



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 605]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 30, 2018/भाद्र 8, 1940

No. 605]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 30, 2018/BHADRA 8, 1940

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 821(अ).— चूंकि वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का XXII) की धारा 14 की अपेक्षानुसार, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय की तारीख 28 फरवरी, 2018 की सा.का.नि. सं.188 (अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (I) में प्रकाशित किए गए, जिसे ऐसे सभी व्यक्तियों जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, से राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए भारत के राजपत्र की प्रतियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गईं;

और चूंकि उक्त अधिसूचना में प्रकाशित राजपत्र की प्रतियां 28 फरवरी, 2018 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी गई थीं;

और चूंकि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर प्रारूप नियमों के बाबत जनता से प्राप्त आक्षेप या सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार उक्त वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का XXII) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम, 2018 है।
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. वायुयान नियम, 1937 (इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा जाए) में, नियम 30 में, उप-नियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाए, अर्थात्:-

“भारत में रजिस्ट्रीकृत उस वायुयान जिस पर केपटाउन अभिसमय या केपटाउन प्रोटोकॉल के उपबंध लागू होते हैं, के रजिस्ट्रीकरण को केंद्रीय सरकार द्वारा इस वायुयान के प्रचालक या किसी अन्य व्यक्ति से सहमति या कोई दस्तावेज़ की मांग किए बिना, पाँच कार्य दिवस के भीतर रद्द किया जा सकेगा, यदि निम्नलिखित के साथ आई डी ई आर ए के धारक से कोई आवेदन प्राप्त हुआ है:-

(i) महानिदेशक से अभिलिखित आई डी ई आर ए की मूल या नोटरीकृत प्रतिलिपि; और

(ii) अंतराष्ट्रीय रजिस्ट्री से प्राप्त प्राथमिक तलाशी रिपोर्ट जिसमें वायुयान में सभी रजिस्ट्रीकृत हित प्राथमिकता के अनुसार दिये गये हों एवं आई डी ई आर ए धारक की ओर से ऐसा प्रमाणपत्र जिसमें प्राथमिक तलाशी रिपोर्ट के अनुसार वायुयान की रैंकिंग में सभी रजिस्ट्रीकृत हितों को प्रभावोन्मुक्त कर दिया गया है या ऐसे हितों के धारक ने उक्त वायुयान के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने या उसका निर्यात करने के लिए सहमति दे दी है;

परन्तु यह तब जब कि उस वायुयान का रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण केंद्रीय सरकार या उसकी कोई संस्था या अंतराष्ट्रीय संगठन जिसमें भारत एक सदस्य है या भारत में लोक सेवा का अन्य प्राइवेट प्रदाता के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा जिससे कि उसके बाबत ऐसे वायुयान द्वारा प्रदान की गई सीधी सेवा से संबंधित भारत सरकार, कोई ऐसी संस्था, संगठन या प्रदाता को देय राशि का भुगतान करने के लिए इसकी विधियों के अधीन उस वायुयान को बंदी बनाया जा सके या निरुद्ध किया जा सके या उसकी कुर्की की जा सके।

स्पष्टीकरण.— इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए “अंतराष्ट्रीय रजिस्ट्री” “केपटाउन अभिसमय के अनुच्छेद 16 के अधीन स्थापित रजिस्ट्री” से अभिप्रेत है.”

3. उक्त नियम के नियम 32 क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम को रखा जाए, अर्थात्:-

“32क. वायुयान का निर्यात.— केंद्रीय सरकार नियम 30 के उप-नियम (7) के अधीन वायुयान के रजिस्ट्रीकरण को रद्द किए जाने के परिणाम-स्वरूप, अतिरिक्त इंजन, यदि कोई हो, सहित वायुयान के निर्यात और भौतिक अदला-बदली को सरल बनाने के लिए निम्नलिखित के अध्याधीन करवाई करेगी यदि उसी वायुयान के निर्यात के लिए आई डी ई आर ए के धारक द्वारा आवेदन किया गया है :-

- (i) वायुयान के बाबत देय बकाया राशि का संदाय; और
- (ii) वायुयान प्रचालन की सुरक्षा संबंधी नियमों और विनियमों का अनुपालन।”

[फा.सं. एवी. 11012/1/2014-ए]

डॉ. शेफाली जुनेजा, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम तारीख 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना: सं बी-26 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (I) में प्रकाशित तारीख 13 जून, 2018 की सा.का.नि. सं. 555 (अ) द्वारा किए गए।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2018

G.S.R. 821(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, was published in the Gazette of India, as required by section 14 of the Aircraft Act, 1934 (XXII of 1934), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation, number G.S.R. 188(E), dated the 28th February, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to public;

And whereas copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 28th February, 2018;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the draft rules within the period specified in the said notification have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the said Aircraft Act, 1934 (XXII of 1934), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely: —

1. (1) These rules may be called the Aircraft (Third Amendment) Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 30, for sub-rule (7), the following shall be substituted, namely:—

“(7) The registration of an aircraft registered in India, to which the provisions of the Cape Town Convention and Cape Town Protocol apply, shall be cancelled by the Central Government, within five working days, without seeking consent or any document from the operator of the aircraft or any other person, if an application is received from the IDERA Holder along with:—

- (i) the original or notarised copy of the IDERA recorded with the Director-General; and
- (ii) a priority search report from the International Registry regarding all Registered Interests in the aircraft ranking in priority along with a certificate from the IDERA Holder that all registered interests ranking in priority to that of the IDERA Holder in the priority search report have been discharged or that the holders of such interests have consented to the deregistration and export of the aircraft:

Provided that such cancellation of registration of the aircraft shall not affect the right of the Central Government or of any entity thereof, or any inter-governmental organisation in which India is a member, or other private provider of public services in India, to arrest or detain or attach or sell an aircraft object under its laws for payment of amounts owed to the Government of India, any such entity, organisation or provider directly relating to the services provided by such aircraft in respect of that object.

Explanation.—For the purpose of this sub-rule, “International Registry” “means the Registry established under Article 16 of the Cape Town Convention”.”.

3. For rule 32A of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

“32A. Export of aircraft. —The Central Government shall, consequent upon cancellation of registration of an aircraft under sub-rule (7) of rule 30, if an application is made by the IDERA Holder for export of the same aircraft, take action to facilitate the export and physical transfer of the aircraft, along with spare engine, if any, subject to: —

- (i) the payment of outstanding dues in respect of the aircraft; and
- (ii) the compliance of the rules and regulations relating to safety of the aircraft operation.”.

[F. No. AV.11012/1/2014-A]

Dr. SHEFALI JUNEJA, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended *vide* G.S.R. 555(E), dated the 13th June, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i).